RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 16 JANUARY TO 22 JANUARY 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 04 ■ अंक 21 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

चुनाव से पहले स्टॉक बनाने में जुटीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां
Page 2

एक से दस रुपये तक के बदलेंगे सभी सिक्के, 20 का आएगा नया सिक्का
Page 5

कुंभ : पंचतत्वों की शुद्धि का विज्ञान
Page 6

editoria!

चुनावी दरियादिली और बैंकों के एनपीए

देश के बैंक वित्तीय एवं बैंकिंग व्यवस्था गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) यानी फंसे हुए कर्जों के भारी दबाव में हैं। अब उनकी चिंता प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बांटे गये ऋण के बड़े हिस्से की वापसी की है। बैंको का अनुमान है यह संकट और भी गंभीर हो सकता है। यह आशंका बे वजह नहीं है। इसके पीछे ठोस कारण है, रिजर्व बैंक की चेतावनी। रिजर्व बैंक ने सरकार को आगाह किया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में फंसे हुए कर्ज की राशि 11 हजार करोड़ रुपये तक जा पहुंची है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में पैदा हुई मुश्किलों का फिलहाल सामना कर रहे वित्तीय तंत्र के लिए यह बेहद चिंताजनक है। उदहारण के लिए ज्यादा दूर नहीं देखना है, पिछले वित्त वर्ष के आखिर में बीमा क्षेत्र के एनपीए में 26 प्रतिशत की बढ़त हुई थी और यह 18 हजार करोड़ से बढ़कर 22,700 करोड़ रुपये हो गया था। आंकड़े कहते हैं मार्च, 2018 तक पूरे बैंकिंग सेक्टर के फंसे हुए कर्ज की राशि 10.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी थी। हालांकि, सरकार और रिजर्व बैंक ने एनपीए की वसूली और इसकी बढ़त पर लगाम लगाने के लिए बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने, नियमों को सख्त बनाने, कर्जदारों पर कड़ाई करने तथा दिवालिया कानून जैसे अनेक कदम उठाये हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ज्यादातर ऐसे कर्ज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों के खाते में हैं। मार्च, 2015 से मार्च, 2018 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए में 6.2 लाख करोड़ की बढ़त हुई है। देश में फंसे हुए कर्ज का आंकड़ा 11.6 प्रतिशत है, जो कि विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बहुत ज्यादा है। सिर्फ रूस ही ऐसा देश है, जिसका हिसाब भारत के बराबर है। चीन में यह1.7, जापान में1.19 , अमेरिका में1.13 , दक्षिण अफ्रीका में 3.10 तथा ब्राजील में 3.9 प्रतिशत है। कुछ महीने पहले भी रिजर्व बैंक ने अंदेशा व्यक्त किया था कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक यानी मार्च, 2019 तक यह आंकड़ा 12 प्रतिशत के पार जा सकता है. लेकिन, 31 दिसंबर को बैंक ने अपने वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में उम्मीद जतायी है कि इसे 10.3 प्रतिशत तक लाया जा सकता है। काश ऐसा ही हो जाये। आंकड़े कहते हैं कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में बैंकों के कर्ज में एनपीए का अनुपात 10.8 प्रतिशत रहने में मुख्य योगदान रिजर्व बैंक की पहलों का नहीं, बल्कि बैंकों द्वारा कर्ज देने और इस्पात उद्योग में बेहतरी का हैं। इस दौरान कर्ज देने में निजी क्षेत्र के बैंक रहे हैं। हालांकि, में रिजर्व बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के संकट तथा सार्वजनिक बैंकों के पास कम पूंजी होने की समस्याओं का संज्ञान गंभीरता से लिया है। लेना भी चाहिए था, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प भी कहाँ था ? सच यह है कि एनपीए के कारण बैंकों द्वारा कर्ज देने में हिचकिचाहट बढ़ी है तथा कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं लंबित हो गई हैं। चूंकि यह समस्या एक लंबे समय में मौजूदा स्तर पर पहुंची है, इसलिए इसके तात्कालिक समाधान की अपेक्षा करना तो व्यर्थ है। लेकिन, एन पी ए कम हो और कम बना रहे , इस कोशिश में तेजी लाने की जरूरत है. इसके लिए ठोस रणनीति, कड़े कदम और पारदर्शिता की दरकार है। आगामी लोकसभा चुनाव को सामने रख कर दिखाई जा रही दरियादिली में इस कारक को नहीं भूलना चाहिए।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लग सकती है आग

कच्चे तेल की कीमतों में और तेज उछाल की आशंका

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान से कच्चे तेल की खरीद पर अब किसी देश को कोई छूट नहीं मिलेगी। इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आने की आशंका बढ़ गई है। ओपेक देशों की कटौती लागू होने से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर पहले ही लौट चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग में ईरान मामलों के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हुक ने कहा कि उनका देश ईरान से तेल निर्यात को पूरी तरह खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है। हुक के मुताबिक, हम अब ईरान को कोई और रियायत नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि उस पर आर्थिक पाबंदियां मजबूत की जाएंगी। उसका 80 फीसदी राजस्व तेल से ही आता है और हम इसे पूरी तरह रोक देंगे, ताकि वह मध्यपूर्व को अस्थिर न कर सके। हुक ने दिसंबर में हुई ओपेक देशों की बैठक के दौरान सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री खालिद अल फालिह से मुलाकात भी की थी। सऊदी और ईरान में तनाव जगजाहिर है। मालूम हो कि मध्य अक्तूबर से दिसंबर के शुरुआत तक कच्चे तेल के दाम 40 फीसदी गिरावट के साथ 50 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद ओपेक देशों ने 12 लाख बैरल रोजाना की उत्पादन में कटौती का फैसला किया और दाम दोबारा 60 डॉलर पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने ईरान से बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए करार को मई 2018 में तोड़ दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान अभी भी आतंकवाद में लिप्त है और अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे है, जिससे मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा है। जबकि ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा के लिए है।

इन वजहों से पहले ही बढ़ रहे दाम

■12 लाख बैरल प्रतिदिन की उत्पादन में कटौती की ओपेक देशों ने ■30% बढ़ी चीन में तेल की मांग दिसंबर में, आर्थिक सुस्ती के बावजूद ■ अमेरिकी शेल ऑयल के उत्पादन में भी कमी दर्ज की गई ■अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी से भी तेल की मांग अच्छी रहने की उम्मीद

ईरान से तेल आयात में पहले ही 60% कमी

चार नवंबर से अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने के बाद ईरान का कच्चा तेल निर्यात 27 लाख बैरल प्रति दिन से होता था, जो अब घटकर दस लाख बैरल प्रति दिन रह गया है। हुक ने अमेरिका ने जिन आठ देशों को ईरान से तेल खरीद की छूट दी थी, उनमें से अब पांच ही उससे आयात कर रहे हैं।

भारत समेत आठ देशों को रियायत

अमेरिका ने भारत, चीन, ताइवान, तुर्की, इटली, यूनान, जापान और दक्षिण कोरिया को ईरान से तेल खरीद पर छूट दे रखी है। इन देशों को छह महीने की छूट मिली थी। हालांकि यह छूट किस तारीख से खत्म होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

अमेरिका-ईरान की लड़ाई में बड़ा दांव, ऐसे कराई भारत को अरबों की कमाई

मुंबई। एजेंसी

एक तरफ अमेरिका और ईरान आपस में बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं भारत सरकार के लिए यह लड़ाई बड़ी कमाई या सेविंग का सौदा साबित हो रही है। भारत जहां ईरान से सब्सिडी पर कच्चा तेल खरीद रहा है, वहीं उसकी कीमत के बदले बड़े स्तर पर सोयामील का निर्यात कर रहा है। स्थिति यह हो गई है कि अगर इसी तरह निर्यात जारी रहता है तो भारत से ईरान के लिए सोयामील का निर्यात 20 गुना बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर इससे सरकार के साथ ही भारत के किसानों को भी फायदा होगा।

सोयामील के सहारे कमाई करेगा भारत

गौरतलब है कि बीते साल नवंबर में ईरान पर लागू अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कई देशों ने उससे कच्चे तेल का आयात करना बंद कर दिया है या काफी कम कर दिया है। हालांकि भारत ने ईरान से कच्चे तेल का आयात जारी रखा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बदले हालात में भारत से ईरान के लिए सोयामील यानी सोयाबीन का निर्यात खासा बढ़ सकता है। इसे ईरान के लिए भी अपने जानवरों की खुराक पूरी करना आसान हो गया है।

चुनाव से पहले स्टॉक बनाने में जुटीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां

नई दिल्ली।एजेंसी

IOC, BPCL और HPCL जैसी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां चुनाव से पहले फ्यूल के रिटेल प्राइसिंग पर वर्चुअल फ्रीज को देखते हुए ऑयल इनवेंटरी बनाने में जुटी हैं। नोटबंद इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के मुताबिक यह बात पेट्रोल और डीजल पर उनके रिकॉर्ड ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन से साफ हो जाता है जो दिसंबर 2018 के अंत में 8.2 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया था।

फ्यूल के रिटेल प्राइस में से रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस और डीलर्स का कमीशन और टैक्स हटाने के बाद जो रकम बचती है वह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन होता है। रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस वह रकम होती है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रिफाइनरी को चुकाती हैं। आमतौर पर ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन 1.5-2.5 रुपये प्रति लीटर होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उनके मार्केटिंग डिवीजन का 60 से 70 पर्सेंट योगदान होता है। दिलचस्प बात यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम तय करते वक्त कैलकुलेशन से रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस को हटा दिया है। इससे ग्रॉस मार्केट मार्जिन तय करने में इनका कंट्रिब्यूशन नहीं होता है।

ऑयल कंपनियों का रिकॉर्ड मार्केटिंग मार्जिन बताता है कि क्रूड ऑयल के दाम में आई गिरावट का पूरा फायदा उन्होंने उठाया है और कंज्यूमर को बहुत थोड़ा लाभ दिया है। इंडियन क्रूड बास्केट का दाम 4 अक्टूबर को 85.1 डॉलर प्रति बैरल के हाई से 28३ नीचे आ चुका है, जबकि इस दौरान फ्यूल के रिटेल प्राइस में सिर्फ 18३ की कमी आई है। इसके चलते ऑयल कंपनियों ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन बढ़कर ?8.2 प्रति लीटर पहुंच गया है जो अक्टूबर 2018 की शुरुआत में लगभग 1 रुपये प्रति लीटर था। सरकार ने ऑयल कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन में कटौती करके फ्यूल के दाम में की गई लगभग एक रुपये प्रति लीटर की कटौती का बोझ उन्हें उठाने के लिए कहा था जिसके चलते उनके स्टॉक में गिरावट आई थी।

ऑयल कंपनियों के मार्केटिंग मार्जिन में कटौती किए जाने के बाद ब्रोकरेज फर्म्स ने उनके स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया था क्योंकि उन्होंने इसे फ्यूल प्राइसिंग में सरकारी दखल माना। हालांकि उनके मार्केटिंग मार्जिन में तेज उछाल आने से इनवेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का एवरेज प्राइस टू बुकवैल्यू मार्केटिंग मार्जिन में कटौती के बाद के 1.87 गुना से घटकर 1.65 गुना पर आ गया।

आमतौर पर देखा गया है कि अहम विधानसभा चुनाव से पहले फ्यूल के रिटेल प्राइस को जस का तस रखा जाता है । इसको देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम ज्यादा ऊपर नीचे होने की सूरत में दाम को स्थिर रखने के लिए इनवेंटरी बनाने में जुटी हैं। ईरान से क्रूड के इंपोर्ट पर लगे प्रतिबंध से मिली छूट मई 2019 में खत्म हो रही है और ओपेक के सबसे बड़े एक्सपोर्टर सऊदी अरब ने एक्सपोर्ट में लगभग 8 लाख बैरल की कमी की है।

कंज्यूमर को दाम में गिरावट का आधा फायदा

ऑयल कंपनियों का रिकॉर्ड मार्केटिंग मार्जिन बताता है कि क्रूड ऑयल के दाम में आई गिरावट का पूरा फायदा उन्होंने उठाया है और कंज्यूमर को बहुत थोड़ा लाभ दिया है। इंडियन क्रूड बास्केट का दाम 4 अक्टूबर को 85.1 डॉलर प्रति बैरल के हाई से 28% नीचे आ चुका है, इस दौरान फ्यूल के रिटेल प्राइस में सिर्फ 18% की कमी आई है।

केबिनेट ने दी BPCL रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय कैबिनेट से BPCL की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार योजना को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया। इनमें सबसे बड़ा फैसला ँइण्थ की विस्तार योजना पर लिया गया है। BPCL की करीब 61 फीसदी हिस्सेदारी वाली नुमालीगढ़ रिफाइनरी के 22,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा IT ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

रिफाइनरी की बढ़ाई जाएगी क्षमता

BPCL रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने पर भी फैसला हुआ है। कोयला और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। रिफायनरी की क्षमता 6 से 8 मिलियन टन तक बढ़ाई जा सकती है। क्षमता बढ़ने से उत्तर-पूर्व की पेट्रोलियम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा. प्रोजेक्ट के 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है।

एग्जिम बैंक को मिली अतिरिक्त पूंजी

केंद्रीय कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला छोटे-मझोले उद्योगों को लेकर दिया गया है। सरकार ने इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए बना एग्जिम (EXIM) बैंक को अतिरिक्त पूंजी के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार एग्जिम बैंक को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराएगी। हालांकि, माना जा रहा था कि अगले दो सालों में सरकार एक्जिम बैंक को अतिरिक्त 6 हजार करोड़ रुपए का पैकेज दे सकती है। पिछले साल भी सरकार ने 500 करोड़ रुपए की पूंजी डाली थी।

घ्ऊ रिटर्न के अगले चरण को मंजूरी

इसके अलावा कैबिनेट ने इनकम टैक्स ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के अगले चरण के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है।

प्रबंधन को 2025 तक रत्नागिरी रिफाइनरी शुरू होने की आशा

मुंबई। एजेंसी

दुनिया की सबसे बड़ी नानर रिफाइनरी परियोजना को स्थापित कर रही रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स को 2020 तक इस पर काम शुरू होने और 2025 तक इस रिफाइनरी के शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि शिवसेना और किसानों की ओर से इस परियोजना का कड़ा विरोध किया जा रहा है। कंपनी का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नवंबर में भाजपा नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय लोगों, मछुआरों और किसानों के विरोध को देखते हुए परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को टाल दिया था। इस परियोजना से इनकी आजीविका छिनने का डर है और उन्हें यहां अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ सत्तासीन पार्टी की गठबंधन सहयोगी शिवसेना का भी समर्थन मिल रहा है। यह परियोजना महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में 15,000 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जानी है। इस पर करीब 3,000 अरब रुपये की लागत आने का अनुमान है और यहां पर सालाना छह करोड़ टन उत्पादन होगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी नए सिरे से स्थापित की जाने वाली रिफाइनरी होगी। शनिवार को कंपनी के मुख्य कार्यकारी बी. अशोक ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कंपनी को 30-40 प्रतिशत स्थानीय लोगों की सहमति मिल गई है। इसका काम समय से 2025 तक खत्म होने की उम्मीद है। इस परियोजना से करीब 14 गांव और 850 परिवार प्रभावित होने की संभावना है।

पेट्रोल हुआ सस्ता, लेकिन आज प्रमुख शहरों में बढ़ गए डीजल के दाम

नई दिल्ली। एजेंसी

आज देश भर में पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, लेकिन डीजल की कीमतों में लगातार सातवें दिन इजाफा देखने को मिला है। बुधवार को सभी प्रमुख महानगरों में पेट्रोल की कीमत 8 पैसा प्रति लीटर तक कम हुई है, जबकि डीजल के दाम 12 से 13 पैसा प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत कम होकर 70.33 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर आ गई है, जबकि मंगलवार को इसके दाम 70.41 रुपये प्रति लीटर रहे थे। जबकि आज यहां डीजल के दाम बढ़कर 64.59 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं जो कि मंगलवार को 64.47 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा था।देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत गिरकर 76 रुपये प्रति लीटर के स्तर के नीचे आ गई है। आज यहां पेट्रोल 75.97 रुपये प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है, जो कि मंगलवार के दाम 76.05 रुपये के मुकाबले 8 पैसा प्रति लीटर कम है। वहीं मुंबई में डीजल के दाम 67.62 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गए हैं, जो कि मंगलवार के दाम 67.49 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 13 पैसे ज्यादा है। वहीं अगर अन्य महानगरों की बात करें तो चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल 8 पैसे सस्ता होकर क्रमश: 73 और 72.44 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। चेन्नई में डीजल 13 पैसे महंगा होकर 68.22 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में डीजल 12 पैसे महंगा होकर 66.36 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं नोएडा में पेट्रोल सस्ता होकर 70.23 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है जबकि बीते दिन इसके दाम 70.29 रुपये प्रति लीटर रहे थे। वहीं आज यहां डीजल की कीमत 63.84 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 63.94 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

जीएसटी सरलीकरण, रीयल एस्टेट के लिये कंपोजीशन योजना की व्यावहारिकता को परखेगा मंत्री समूह

नई दिल्ली। एजेंसी

गुजरात के उप- मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रीस्तरीय समूह रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिये कंपोजीशन योजना के साथ साथ जीएसटी दरों के सरलीकरण की संभावनाओं पर विचार करेगा। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की 10 जनवरी को हुई बैठक में जीएसटी व्यवस्था के तहत रीयल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये सात सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का फैसला किया गया था।

वित्त मंत्रालय के यहां जारी वक्तव्य में मंत्री समूह की संदर्भ शर्तों में अन्य बातों के अलावा रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिये एक कंपोजीशन योजना बनाना भी शामिल है। मंत्री समूह रीयल एस्टेट क्षेत्र पर लागू जीएसटी दरों के सरलीकरण का भी विश्लेषण करेगा। इसके साथ ही समूह रीयल

एस्टेट क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर भी गौर करेगा। मंत्री समूह रीयल एस्टेट क्षेत्र में भूमि तथा विभिन्न प्रकार की अन्य सामग्री को कंपोजीशन योजना में शामिल करने अथवा अलग रखने की वैधानिकता की भी जांच परख करेगा साथ ही उसकी मूल्यांकन प्रणाली के बारे में भी सुझाव देगा। रीयल एस्टेट क्षेत्र पर गठित इस मंत्री समूह में शामिल अन्य मंत्रियों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, तथा गोवा के पंचायत मंत्री माउविन गोदिन्हो शामिल हैं। वर्तमान में निर्माणाधीन संपत्तियों और ऐसे तैयार फ्लैट जहां बिक्री के समय कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया, उनके भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है। इस तरह की संपत्तियों पर जीएसटी लागू होने से पहले 15 से 18 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था। बहरहाल, ऐसी रीयल एस्टेट संपत्ति जिसके लिये बिक्री के समय कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी हो चुका है, उनके खरीदारों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ऐसी शिकायतें मिलीं हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद बिल्डर संपत्तियों के दाम में कमी लाकर ग्राहकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दे रहे हैं।

GST चोरी रोकने के लिए ई-वे बिल से जोड़ा जाएगा फास्टैग

नई दिल्ली। एजेंसी

जीएसटी का ई-वे बिल सिस्टम अप्रैल तक एनएचएआई के फास्टैग मैकेनिज्म से जोड़ा जा सकता है। इससे माल की आवाजाही पर नजर रखने और जीएसटी चोरी पर काबू पाने में आसानी होगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ई-वे बिल, फास्टैग और डीएमआईसी की लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। यह काम उसने ट्रांसपोर्टर्स से सलाह-मशविरे के बाद किया है।

एक अधिकारी ने बताया, 'हमारे ध्यान में यह बात आई है कि कुछ ट्रांसपोर्टर एक ही ई-वे बिल जेनरेट कर कई ट्रिप लगा रहे हैं। ई-वे बिल को फास्टैग से जोड़ देने से गाड़ी की लोकशन पता करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह भी पता लगाया जा सकेगा कि कब और कितनी बार वह गाड़ी एनएचएआई के टोल प्लाजा से गुजरी।' अधिकारी ने बताया कि अप्रैल से यह सिस्टम पूरे देश में लागू करने की योजना है।

कर्नाटक पायलट बेसिस पर इंटीग्रेटेड सिस्टम लागू कर रहा है। नेशनल लेवल पर इस इंटीग्रेशन से काफी फायदा होगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ई-वे बिल सही ट्रैवल पीरियड के लिए जेनरेट किया गया। अधिकारी ने बताया, 'अधिकारियों क समिति सभी संबंधित पक्षों को इसके फायदे समझाएगी।' उन्होंने कहा कि इस कदम से देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की कामकाजी कुशलता बढ़ेगी। अभी 'ट्रैक एंड ट्रेस' मैकेनिज्म के तहत विभिन्न एजेंसियों के बीच जानकारी की साझेदारी ठीक से नहीं हो पाती, जिससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा इसके चलते ई-वे बिल का दुरुपयोग भी हो रहा है।

क्या होगा फायदा

अधिकारी ने कहा, 'इससे बेईमान ट्रेडर सप्लाई चेन में लूपहोल्स का फायदा उठाकर जीएसटी चोरी नहीं कर पाएंगे।' सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स ने अप्रैल से दिसंबर तक जीएसटी चोरी या इसके नियमों के उल्लंघन के 3626 मामले पकड़े हैं। ये 15278.18 करोड़ रुपये के मामले हैं। ई-वे बिल सिस्टम पहली अप्रैल 2018 को लागू किया गया था। यह एक से दूसरे राज्य में जाने वाले 50000 रुपये से ज्यादा मूल्य के माल के लिए है। राज्य के भीतर माल की आवाजाही पर यही सिस्टम चरणबद्ध तरीके से 15 अप्रैल से लागू किया गया था। 50000 रुपये से ज्यादा का माल ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को ढुलाई के दौरान मांगे जाने पर जीएसटी इंस्पेक्टर को ई-वे बिल दिखाना होता है।

अधिकारी ने कहा, 'फास्टैग और एलडीबी से ई-वे बिल सिस्टम को जोड़ने से कैश बेसिस पर अभी हो रहे ट्रेड पर रोक लगाई जा सकेगी, जिससे टैक्स कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है।'नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल कलेक्ट करने के लिए फास्टैग सिस्टम शुरू किया है। फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती। ई-वे बिल से फास्टैग को जोड़ देने पर रेवेन्यू अथॉरिटीज को गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखने और यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि वे उसी जगह जा रही हैं, जिसका जिक्र ट्रांसपोर्टर या ट्रेडर ने ई-वे बिल जेनरेट करते वक्त किया था।

मुद्रास्फीति में नरमी

मौद्रिक नीति समिति फरवरी में अपना सकती है उदार रुख

मुंबई। एजेंसी

खुदरा और थोक मुद्रास्फीति में नरमी को देखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति अपनी अगली बैठक में नीतिगत ब्याज दर के बारे में अपना रुख नरम कर सकती है। वित्तीय सेवा क्षेत्र के बारे में एक रपट में यह अनुमान लगाया गया है। आरबीआई ने अभी मौद्रिक नीति के बारे में 'नाप-तोल कर सखी' करने का रुख अपना रखा है। कोटक की अनुसंधान रपट का कहना है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति के और नरम पड़ने के बाद अपने रुख को 'तटस्थ' कर सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर दिसंबर में गिर कर 2.19 प्रतिशत पर आ गयी थी जो एक माह पहले 2.33 प्रतिशत और दिसंबर 2017 में 5.21 प्रतिशत थी। यह खुदरा मुद्रास्फीति का 18 माह का न्यूनतम स्तर है। इसी तरह थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति भी दिसंबर में 3.80 प्रतिशत पर आ गई। यह इसका आठ माह का न्यूनतम स्तर है। इससे एक माह पूर्व थोक मुद्रास्फीति 4.64 प्रतिशत और दिसंबर 2017 में 3.58 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के निर्धारण में खुदरा मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। यह लगातार पाचवां माह है जबकि यह 4 प्रतिशत से नीचे है। रिजर्व बैंक के सामने इसे चार प्रतिशत के आसपास बनाए रखने का लक्ष्य दिया गया है। रपट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति की नरमी को देखते हुए " हमारा यह ठोस मत है कि फरवरी की बैठक में मुद्रा स्फीति समिति अधिक उदार रुख अपनाएगी और अपने नीतिगत रुख को "नाप तोल कर कठोर करने" की जगह 'तटस्थ' कर सकती है।

अमेरिका से हर साल पांच अरब डॉलर के तेल, गैस खरीदेगा भारतः राजदूत

वॉशिंगटन। एजेंसी

भारत, अमेरिका से सालाना पांच अरब डॉलर (करीब 3.50 खरब रुपये) के तेल और गैस खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। एक शीर्ष भारतीय राजनयिक ने दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग का जिक्र करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत, अमेरिका से 18 अरब डॉलर (करीब 5.60 खरब रुपये) के रक्षा उपकरण की खरीदी पर भी विचार कर रहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को कहा कि भारत में अमेरिका का निर्यात कम-से-कम 30 प्रतिशत तक बढ़ा है। उन्होंने अमेरिका के व्यापारिक समुदाय को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में द्विपक्षीय सहयोग 119 अरब डॉलर (करीब 83.30 खरब रुपये) से बढ़कर 140 अरब डॉलर (98 खरब रुपये) करीब हो गया है। राजदूत के सम्मान में अमेरिका-भारत व्यापार परिषद यानी यूएसआईबीसी (USIBC) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में श्रृंगला ने कहा कि भारत, अमेरिका से अब तक की सबसे अधिक खरीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत केवल तेल और गैस के क्षेत्र में ही अमेरिका से हर साल पांच अरब डॉलर की खरीद को लेकर प्रतिबद्ध है। बकौल श्रृंगला रक्षा क्षेत्र में भारत 18 अरब डॉलर के ऑर्डर पर विचार कर रहा है और यह प्रक्रिया में है।

श्रृंगला ने कहा कि भारत की व्यावसायिक विमानन कंपनियों ने 40 अरब डॉलर (करीब 28 खरब रुपये) मूल्य के 300 विमानों के ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने कहा, 'हम ऐसे उत्पादों के आयात पर भी विचार कर रहे हैं, जिन्हें हमने पहले कभी अमेरिका से नहीं खरीदा है।' राजदूत ने कहा कि भारत में अमेरिका की कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारत के योगदान के बारे में राजदूत ने कहा कि वर्तमान में 2 लाख 27 हजार भारतीय छात्र अमेरिका के अकादमिक क्षेत्र में 6.5 अरब डॉलर (4.55 खरब रुपये) का योगदान कर रहे हैं।

साख निर्धारण एजेंसियां अपनी भूमिका पर गौर करें : वित्तीय सेवा सचिव

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आईएल एंड एफएस जैसी कंपनियों के वित्तीय संकट को देखते हुए रेटिंग एजेंसियों को अपनी भूमिका पर गौर करने की जरूरत है। गौरतलब है कि रेटिंग एजेंसियां इस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रिण चुकाने में चूक करने के ठीक पहले तक निरंतर निवेश श्रेणी की उच्चतम रेटिंग देती रहीं। आईएल एंड एफएस ने पिछले साल अगस्त की शुरूआत से कई बार भुगतान में चूक की जिससे वित्तीय और पूंजी बाजारों को तगड़ा झटका लगा। रेटिंग एजेंसियां आईएल एंड एफएस के बढ़ते कर्ज और उभरते वित्तीय संकट को भांपने में विफल रही। कई बार चूक को देखते हुए साख निर्धारण एजेंसियां जांच के घेरे में हैं। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि जहां एक तरफ बैंक फंसे कर्ज की समस्या से निपटने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ एनबीएफसी ने आक्रमक तरीके से कर्ज देने में लगी थी। उन्होंने कहा, ''बैंक जब फंसे कर्ज की समस्या से निपटने में लगे थे, एनबीएफसी में वृद्धि तेजी से हो रही थी। जिस प्रकार बैंकों ने आक्रमक तरीके से कर्ज दिये और जो स्थिति हुई, वही एनबीएफसी की हुई।'' कुमार ने कहा, ''कुछ एनबीएफसी में सामान्य से अधिक वृद्धि देखी गयी। उनमें संपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही अत्यधिक गहन तरीके से नियमन की जरूरत है। रेटिंग एजेंसियों की भूमिका पर विचार की आवश्यकता है और यह देखने की जरूरत है कि कैसे इन्हें 'एएए' कर रेटिंग मिली हुई थी और अचानक से ये एक दिन में आठ पायदान नीचे आ गये। इन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है।'' बाद में आइएल एंड एफएस की रेटिंग को कम कर कबाड़ की श्रेणी में डाल दिया गया। एनबीएफसी के ऊपर करीब 91,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसमें से 57,000 करोड़ रुपये बैंकों का कर्ज है। कर्ज देने वालों में ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों में बेहतर कंपनी गतिविधियां लाने के प्रयास के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार की हिस्सेदारी कम कर 52 प्रतिशत पर लाने की सलाह दी है। कुमार ने कहा, ''सरकार एक प्रमुख हिस्सेदार है। इसीलिए इसमें बेहतर कंपनी गतिविधियां लाने की जरूरत है। पहले चरण में हिस्सेदारी को कम कर कम-से-कम 52 प्रतिशत पर लाने की जरूरत है। जब भी बाजार की स्थिति बेहतर होती है, बैंक इस दिशा में कदम उठाएंगे। उनके पास सभी प्रकार की मंजूरी है।''

एक्सपोर्ट ग्रोथ सुस्त, ट्रेड घाटा 10 महीने में सबसे कम

दिसंबर में एक्सपोर्ट ग्रोथ 0.34% रही, इंपोर्ट में 2.4% की गिरावट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश का निर्यात दिसंबर में स्थिर रहा, लेकिन इंपोर्ट में कमी आने से ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा के मोर्चे पर राहत मिली। यह दिसंबर में 10 महीनों के निचले स्तर पर रहा। पिछले महीने एक्सपोर्ट 0.34 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 27.9 अरब डॉलर का रहा, जबकि इंपोर्ट 2.4 पर्सेंट की गिरावट के साथ 41.01 अरब डॉलर पर आ गया। इससे ट्रेड डेफिसिट घटकर 13.08 अरब डॉलर हो गया, जो सालभर पहले इसी महीने में 14.2 अरब डॉलर था। वहीं, नवंबर 2018 में ट्रेड डेफिसिट 16.67 अरब डॉलर रहा था। यह जानकारी सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी किए गए डेटा से मिली है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं और इससे ग्लोबल ट्रेड पर बुरा असर पड़ा है। भारत के निर्यात में बढ़ोतरी न होना इसी ट्रेंड के मुताबिक है। चीन का निर्यात भी दिसंबर में 4.4 पर्सेंट की गिरावट के साथ दो साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (फियो) के प्रेसिडेंट गणेश कुमार गुप्ता ने कहा, 'निर्यात में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल ट्रेड वॉर का भी भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। इससे आयात भी प्रभावित हो रहा है।' वित्त वर्ष 2019 में अप्रैल से दिसंबर के बीच निर्यात 10.2 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ 245.5 अरब डॉलर का रहा, जबकि इस बीच आयात 386.7 अरब डॉलर रहा। साल भर पहले की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में 12.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2019 के पहले 9 महीनों में व्यापार घाटा 141.2 अरब डॉलर का रहा, जो साल भर पहले की इसी अवधि में 120.6 अरब डॉलर रहा था। दिसंबर महीने में रुपये में एक्सपोर्ट ग्रोथ 10.5 पर्सेंट रही। इसमें डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी की बड़ी भूमिका थी। पिछले महीने रुपये में आयात 7.41 पर्सेंट बढ़ा।

लेदर, जेम्स एंड ज्वैलरी, हाथ से बने कपास के धागों और दवाओं के में गिरावट से निर्यात पर बुरा असर पड़ा। ये वैसे सेक्टर हैं, जिनसे लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। प्रमुख जिंसों में दिसंबर महीने में एक्सपोर्ट ग्रोथ पॉजिटिव रही। पिछले महीने पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स का निर्यात 13.18 पर्सेंट, ऑर्गेनिक और इन-ऑर्गेनिक केमिकल्स का 5.5 पर्सेंट और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्यात 50.81 पर्सेंट बढ़ा। आधिकारिक डेट के मुताबिक, 30 में से 17 सेक्टर में एक्सपोर्ट में गिरावट आई।

वायदा कारोबार में सोना 87 रुपये तेज

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सटोरियों के सौदे बढ़ाने के साथ वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख से वायदा कारोबार में बुधवार को सोना 87 रुपये तेज होकर 30,859 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में

फरवरी डिलिवरी वाला सोना 87 रुपये यानी 0.27 प्रतिशत बढ़कर 30,859 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। इसमें 676 लॉट का कारोबार हुआ। इसी प्रकार, अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 88 रुपये यानी 0.27 प्रतिशत बढ़कर 32,391 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। इसमें 115 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि प्रतिभागियों के सौदे करने और डॉलर में कमजोरी से वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं में मजबूत रुख से यहां वायदा कारोबार में सोने के भाव में तेजी रही। वैश्विक स्तर, सिंगापुर में सोना 0.11 प्रतिशत बढ़कर 1,228 डॉलर प्रति औंस पर रहा।

सरकार ने राष्ट्रीय हवाई माल परिवहन नीति पेश की

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने मंगलवार को बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय हवाई माल परिवहन (एयर कार्गो) नीति पेश की। इसमें देश को 2025 तक शीर्ष पांच हवाई माल परिवहन बाजार में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यहां दो दिवसीय वैश्विक विमानन सम्मेलन 2019 के दौरान नीति दस्तावेज जारी किया गया। नीति में तीनों श्रेणी...घरेलू कार्गो, अंतरराष्ट्रीय कार्गो तथा पारगमन अंतरराष्ट्रीय कार्गो.. को शामिल किया गया है। इसमें अन्य बातों के अलावा अगले छह साल में सभी बड़े हवाईअड्डों पर हवाई माल परिवहन केंद्र सृजित करने पर जोर दिया गया है।

देश का कच्चा इस्पात उत्पादन दिंसबर में 1.4 प्रतिशत गिरा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन दिसंबर में 1.4 प्रतिशत घटकर 89.36 लाख टन रहा। दिसंबर 2017 में यह आंकड़ा 90.67 लाख टन था। संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) ने अपनी नवीनतम रपट में कहा, '' कच्चा इस्पात उत्पादन दिसंबर 2017 की तुलना में 1.4 प्रतिशत घटकर दिसंबर 2018 में 89.36 लाख टन रहा। जबकि नवंबर 2018 के मुकाबले उत्पादन में 0.3 प्रतिशत की कमी आयी है।'' अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की सेल, राष्ट्रीय इस्पात निगम, टाटा स्टील, एस्सार स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदर स्टील एंड पावर का संयुक्त उत्पादन 4.75 करोड़ टन रहा। जबकि अन्य कंपनियों का उत्पादन 3.15 करोड़ टन था। रपट में कहा गया है कि दिसंबर 2018 में गर्म धातु का उत्पादन 2.6 प्रतिशत बढ़कर 61.58 लाख टन रहा जो दिसंबर 2017 में 60.01 लाख टन था। वहीं पिग लौह का उत्पादन 5.5 प्रतिशत घटकर 5.30 लाख टन रहा जो पिछले साल दिसंबर में 5.61 लाख टन था। जेपीसी, इस्पात मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है जो लौह एवं इस्पात उद्योग से जुड़े आंकड़े जुटाती है। भारत ने 2030-31 तक उत्पादन क्षमता 30 करोड़ टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

'अंकुश' लगाने वाली खुदरा FDI नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : रिपोट

मुंबई। एजेंसी

घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति पर 'अनिवार्य' रूप से पुनर्विचार करने की जरूरत बताई, क्योंकि देश के खुदरा क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद होने के बावजूद अच्छा निवेश नहीं आ रहा है। इक्रा का मानना है कि मौजूदा एफडीआई नीति 'अंकुश' लगाने वाली है। इसी तरह की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की समान चिंताओं का उदाहरण देते हुए एजेंसी ने कहा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र का खुदरा कारोबार साथ काम कर सकता है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति अभी भी 'अंकुश' वाली बनी हुई है। मौजूदा समय में 51 प्रतिशत मालिकाना हक, बुनियादी क्षेत्र पर अनिवार्य निवेश की शर्तें और स्थानीय स्तर पर सामान खरीदने की शर्तें एफडीआई नीति का हिस्सा हैं। इक्रा के उपाध्यक्ष और कॉरपोरेट क्षेत्र रेटिंग के सह-प्रमुख किंजल शाह ने कहा कि सरकार को अनिवार्य रूप से एफडीआई नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र में निवेश की जरूरतें काफी व्यापक हैं। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से 2018 के बीच भारतीय खुदरा क्षेत्र में 1.4 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ तो देश को मिले कुल एफडीआई निवेश का मात्र 0.36 प्रतिशत है।

एक से दस रुपये तक के बदलेंगे सभी सिक्के, 20 का आएगा नया सिक्का

कानपुर। एजेंसी

बीस रुपये का सिक्का या फिर नोट? क्या लाया जाए? लंबे मंथन के बाद आखिरकार तय हो गया कि सिक्का लाया जाएगा। अब नोट की जगह बीस का नया नवेला सिक्का जारी होगा। यही नहीं भारत सरकार एक रुपये से लेकर दस रुपये तक के सभी सिक्कों का कलेवर भी बदलने जा रही है। इन सिक्कों के प्रोटोटाइप यानी डिजाइन तैयार हो गए हैं, जिन्हें फाइनल करने के लिए आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नई डिजाइन वाले सिक्कों के साथ बीस रुपये के नए सिक्के की भी भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 के तहत वैधानिकता के संबंध में अहम निर्णय होंगे। बीस का सिक्का अष्टकोणीय आकार का हो सकता है।

दृष्टिबाधित दिव्यांग भी आसानी से पहचान पाएंगे

दैनिक जागरण को मिली जानकारी के मुताबिक सिक्के इस प्रकार ढाले जाएंगे कि दृष्टिबाधित दिव्यांग इन्हें आसानी से पहचान सकें। भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के अनु सचिव ने इस संबंध में पत्र जारी कर सिक्कों की डिजाइन फाइनल करने से संबंधित लोगों की बैठक बुलाई है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक बीस रुपये के नोट जारी करने की तैयारी कर रही थी, जिसकी डिजाइन अंतिम चरण में थी। माना जा रहा है कि कागज की खपत को देखते अभी सिक्कों को ही जारी किया जाएगा। ऐसे में आरबीआइ अभी बीस रुपये के नए नोट जारी करने से रुक सकती है।

मार्च 2019 तक 26 हजार करोड़ रुपये के सिक्के होने का अनुमान

भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड-एसपीएमसीआइएल) ने इससे पहले वर्ष 2011 में सिक्कों की डिजाइन में बदलाव किया था। इसे 'भारतीय सिक्कों की नई श्रृंखला 2011' कहा गया था। तब 50 पैसे से लेकर दस रुपये तक, सभी सिक्कों में रुपये का चिह्न् शामिल किया गया था। भारतीय बाजार इस समय सिक्कों के बोझ तले दबा हुआ है। मार्च 2018 तक भारतीय बाजार में कुल 25,600 करोड़ रुपये के सिक्के प्रचलित थे, जिनके मार्च 2019 तक बढ़कर 26 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

सामाजिकता का संदेश भी देंगे सिक्के

भारत सरकार से जुड़ी शेप एंड साइज संस्था सिक्कों की डिजाइन के बारे में विशेषज्ञों से सुझाव लेती है। फिर डिजाइन को फाइनल किया जाता है। इन कमेटियों में मुद्रा, कला, विज्ञान, संस्कृति और समाज से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन (एनआइडी) से भी सुझाव लिए जाते हैं। माना जा रहा है, नए सिक्कों की डिजाइन में एनआइडी अहमदाबाद ने अहम सुझाव दिए हैं। नए कलेवर के सिक्के सामाजिकता का संदेश भी देंगे। इन सिक्कों में भारत सरकार द्वारा चलाए गए सामाजिक सरोकार के अभियानों को शामिल किया है।

18 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई, ब्याज दरों में कटौती कर सकता है RBI!

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

खाने-पीने के सामान की कीमतों में आई गिरावट और ईंधन के दाम में हुई मामूली बढ़ोतरी की वजह से दिसंबर महीने खुदरा महंगाई में जबरदस्त गिरावट आई। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2018 में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) कम होकर 2.19 फीसद हो गई, जो 18 महीनों का न्यूनतम स्तर है। पिछले एक महीनों के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 30 फीसद से अधिक की गिरावट आई है।

रॉयटर्स के पोल्स में विश्लेषकों ने दिसंबर महीने के लिए 2.20 फीसद महंगाई दर का अनुमान लगाया था। नवंबर में खुदरा महंगाई 2.33 फीसद रही है।

दिसंबर में थोक महंगाई भी कम होकर 8 महीनों के निचले स्तर पर जा चुकी है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दिसंबर में 3.80 फीसद रही। नवंबर में थोक महंगाई 4.64 फीसद थी, जबकि दिसंबर 2017 में यह 3.58 फीसद रही थी। महंगाई में लगातार आई कमी के बाद अगले महीने होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ब्याज दरों में कटौती को लेकर विचार कर सकता है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई सुस्ती की वजह से आर्थिक गतिविधियों को गहरा धक्का लगा है। गौरतलब है कि कोर सेक्टर में आई सुस्ती से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक विकास की दर को झटका लगा है। मैन्युफैक्यरिंग सेक्टर विशेषकर कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स सेक्टर के ग्रोथ में आई सुस्ती की वजह से औद्योगिक उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई है।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) कम होकर 0.5 फीसद हो गया, जो 17 महीनों का निचला स्तर है। पिछले साल के दौरान इसी महीने में आईआईपी 8.5 फीसद रहा था। औद्योगिक गतिविधियों में आई सुस्ती के बाद एसबीआई कैपिटल की रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआई के जीडीपी अनुमान को कम करने की सलाह दी गई है। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई को चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी अनुमान को घटाकर 7 फीसद करना चाहिए। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए 7.4 फीसद जीडीपी का अनुमान लगा रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'हम उम्मीद करते हैं कि मौद्रिक समिति में शामिल सदस्य वास्तविक स्थिति को समझेंगे और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में आई सुस्ती की स्थिति को स्वीकार करेंगे।' अर्थशास्त्री अर्जुन नागराजन और अमोल बोर ने लिखा है, 'औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ें सदस्यों को जीडीपी के पूर्वानुमान के आंकड़ों पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य करेगा।' कमजोर वृद्धि दर और आरबीआई के लक्ष्य से महंगाई दर के दो फीसद नीचे रहने के बाद इस साल ब्याज दरों में कटौती की मांग उठ सकती है।

'आधार' अपडेट कराने को अब देने होंगे 50 रुपये, सेफ्टी फीचर भी बढ़े

लखनऊ। एजेंसी

आधार बनाने की प्रक्रिया को अब और पुख्ता करने की तैयारी है। आधार का डाटा सुरक्षित रखने के लिए अब जहां कई सेफ्टी फीचर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं आधार को अपडेट कराने के लिए उसका शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही एक से अधिक बार आधार में संशोधन कराने के लिए डाकघरों की जगह रीजनल यूआइडीएआइ (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के ऑफिस जाना होगा। अब बॉयोमीट्रिक अपडेट के लिए 50 रुपये देने होंगे। पहले इस काम केलिए केवल 30 रुपये देने पड़ते थे। इसके अलावा ई-केवाइसी के लिए 30 रुपये देने होंगे। आधार का ए-4 साइज पेपर पर कलर प्रिंट करवाने पर 30 रुपये देने होंगे। वर्ष 2011 में आधार कार्ड बनने की शुरुआत हुई थी। उस दौरान आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष ही आता था। जबकि वर्ष 2016 में यूआइडीएआइ ने कार्ड में बदलाव किया और इसमें जन्म तिथि को शामिल कर लिया। अब यूआइडीएआइ ने सुरक्षा को देखते हुए एक बार से अधिक संशोधन डाकघरों में नहीं कराने के आदेश दिए हैं। अगर आधार पर जन्म की तारीख और वर्ष संबंधी गलती होगी तो पहली बार आधार सेंटर पर जाकर या ऑनलाइन इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन दूसरी बार किसी तरह का बदलाव करने के लिए गोमतीनगर स्थित क्षेत्रीय यूआइडीएआइ ऑफिस जाना होगा। जन्मतिथि में संशोधन के लिए अपने साथ हाईस्कूल की मार्कशीट लेकर जाना होगा।

सुरक्षा के खास इंतजाम- अब आधार बनाने के दौरान डाक विभाग के कर्मचारियों की जगह यूआइडीएआइ के पास वन टाइम पासवर्ड जाएगा। साथ ही आधार बनाने वाले उपकरणों में खराबी होने पर उसकी मरम्मत भी यूआइडीएआइ की टेक्निकल टीम करेगी।

महंगे आईफोन के देश में घटे कद्रदान, एक साल में शिपमेंट आधी हुई

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में एपल आईफोन की बिक्री पहले से काफी कम हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक 2017 की तुलना में साल 2018 में आईफोन शिपमेंट में आधे से भी ज्यादा की कमी आई। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में 2014 के बाद से यह कंपनी का सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे एपल की परेशानी और बढ़ गई है, जिससे उसे अपने रेवेन्यू आउटलुक में कटौती करने को मजबूर होना पड़ा है।

हांगकांग की कंपनी काउंटरप्वाइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के मुताबिक 2018 में एपल का इंडिया शिपमेंट 16 से 17 लाख के बीच रहा। सायबरमीडिया रिसर्च के मुताबिक यह करीब 20 लाख था। हालांकि ये दोनों आंकड़े 2017 के 32 लाख यूनिट्स से कम हैं। एनालिस्ट्स ने बताया कि आईफोन शिपमेंट घटने की वजह यह है कि ये फोन बहुत महंगे हैं। वनप्लस जैसी चीन की कंपनियां आईफोन की एक तिहाई कीमत में उससे बेहतर फीचर्स वाले स्मार्टफोन बेच रही हैं।

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर नील शाह ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच एपल ने करीब 4,00,000 आईफोन भारत भेजे थे। अगर इसकी तुलना प्रीमियम सेगमेंट के लीडर वनप्लस से करें, तो उसने इस बीच करीब 5,00,000 फोन भारतीय बाजार में उतारे। उन्होंने बताया, '2017 तक एपल की शिपमेंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन 2018 में इसके 2014-15 के बराबर रहने का अनुमान है। इससे कंपनी 3 साल पीछे चली गई है, जबकि इस बीच मार्केट का 50 पर्सेंट से ज्यादा विस्तार हुआ है।' 2014 की तुलना में 2018 में स्मार्टफोन की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है। 2014 में 8 करोड़ यूनिट्स की बिक्री होती थी, जबकि 2018 में यह बढ़कर 15 करोड़ यूनिट्स हो गई है। काउंटरप्वाइंट के मुताबिक इसकी तुलना में एपल की शिपमेंट आज 16-17 लाख यूनिट्स है, जो 2014 में 15 लाख यूनिट्स थी।

एनालिस्ट्स ने बताया कि 2018 में एपल की शिपमेंट में गिरावट के पीछे मार्केट में कड़ा कॉम्पिटीशन और आईफोन के नए मॉडल्स का बहुत महंगा होना है। 1,000 डॉलर से ज्यादा की कीमत वाले इन नए आईफोन की बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी ने ईएमआई स्कीम, जीरो डाउनपेमेंट्स और कैशबैक जैसे कई ऑफर्स दिए, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम कस्टमर्स ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। एनालिस्ट्स ने बताया कि यहां तक कि आईफोन 8 और 8 प्लस जैसे पुराने मॉडल पर भी इन ऑफर्स से निराशा हाथ लगी।

कुंभ पर विशेष

सद्गुरु

कुंभ: पंचतत्वों की शुद्धि का विज्ञान

हिंदू दर्शन में यह सृष्टि पंचभूतों- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश- से बनी है। हमारा शरीर भी इन्हीं पंचभूतों से बना है। इन पांच तत्वों का महत्व अगर हम ठीक से समझ जाएं, तो हम भी पूरी तरह से ठीक रहेंगे। कुंभ इन पंचभूतों की शुद्धि का एक महान अवसर है। जैसा कुछ लोग मानते हैं, इसे केवल मेला नहीं समझें।

इस कुंभ को ज्ञान के एक आधार के रूप में पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इसे एक ऐसे स्थान के रूप में रूपांतरित करने की जरूरत है, जहां बड़ी तादाद में लोग इसे प्रेरणा के स्रोत के तौर पर देख सकें, इसे रूपांतरण करने वाले और आरोग्यवर्धक अवसर के तौर पर ले सकें, जैसा हजारों सालों से होता आ रहा है।

आखिर बारह सालों में एक बार यहां नहाने का क्या महत्व है? इसका संबंध योग के एक मूलभूत पहलू से है, जिसे भूत शुद्धि कहा जाता है और जिसका अर्थ है, अपने पंचतत्वों की सफाई करना।

इस सृष्टि में जो कुछ भी है, वह सब पंचतत्वों का ही खेल है। यह दिखाता है कि इस सृष्टि के निर्माण के पीछे किस तरह की बुद्धिमत्ता है। जीवन के अरबों-खरबों रूप सिर्फ पांच तत्वों से ही बने हैं। इसीलिए योग के मूलभूत अंग- भूत शुद्धि में, ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन पांच तत्वों पर अपना अधिकार कर लें, तो आपका स्वास्थ्य, कल्याण, समृद्धि जैसी तमाम चीजों की देखभाल अपने आप होती रहती है।

इस शरीर की जो संरचना है, वह कुछ इस तरह की है कि इसमें 72 फीसदी पानी है, 12 फीसदी पृथ्वी है, छह फीसदी वायु है, चार फीसदी अग्नि है, बाकी आकाश है। किसी इनसान के लिए यहां अच्छी तरह से रहने के लिए पानी की बड़ी अहमियत है, क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा पानी होता है। इस धरती का भी 72 फीसदी हिस्सा पानी ही है, इसलिए कुंभ या कुछ विशेष अक्षांशों पर नदियों के मिलने की घटना का जो हम उपयोग कर रहे हैं, वह किसी मान्यता की वजह से नहीं है, न ही यह कोई अंधविश्वास है। जीवन और दूसरी शक्तियां हमारे आसपास कैसे काम करती हैं, हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके गहन विश्लेषण से यह सब परंपरा बनी है।

> प्राचीन समय में हर कोई जानता था कि 48 दिनों के मंडल के दौरान अगर आप कुंभ में रुकें और हर दिन जरूरी साधना के साथ उस पानी में जाएं, तो अपने शरीर को, अपने मनोवैज्ञानिक तंत्र को, अपने ऊर्जा तंत्र को रूपांतरित कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, बस 40 दिन रोज 10-12 मिनट की साधना कीजिए और उसके बाद कुंभ में आकर स्नान कीजिए।

आधुनिक विज्ञान भी अब इस ओर देख रहा है। भूमध्य रेखा यानी शून्य डिग्री अक्षांश और तीस डिग्री अक्षांश के बीच धरती के घूमने से पैदा होने वाला अपकेंद्रीय बल ज्यादातर लंबवत रूप में काम करता है। ग्यारह डिग्री अक्षांश पर यह पूरी तरह से लंबवत होता है। धरती का अपकेंद्रीय बल हर चीज को ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो शून्य से लेकर तीस डिग्री अक्षांश के बीच की जगह को इस धरती पर पवित्र माना गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी साधना की जाती है, उसका अधिकतम लाभ मिलता है। इन अक्षांशों के बीच हमने कई जगहों की पहचान की, जहां साल में या एक सौर्य वर्ष में, जो बारह वर्ष तीन महीनों का होता है, अलग-अलग समय पर तमाम शक्तियां एक खास तरीके से काम करती हैं। बस इन्हीं जगहों को किसी खास दिन या दिनों के लिए चुना गया।

जहां कहीं भी पानी के दो निकाय एक खास बल के साथ मिलते हैं, वहां पानी का मंथन होने लगता है। जैसा मैंने कहा हमारे शरीर में भी 72 फीसदी पानी है। तो यह शरीर जब किसी खास समय और नक्षत्र में वहां पर होता है, तो उसे अधिकतम लाभ मिलता है।

प्राचीन समय में हर कोई यह जानता था कि 48 दिनों के मंडल के दौरान अगर आप कुंभ में रुकें और हर दिन आप जरूरी साधना के साथ उस पानी में जाएं, तो आप अपने शरीर को, अपने मनोवैज्ञानिक तंत्र को अपने ऊर्जा तंत्र को रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हर किसी के लिए कम से कम 40 दिनों की साधना का एक कार्यक्रम तय कर दें। आप जहां कहीं भी हैं, बस 40 दिन तक रोजाना 10 से 12 मिनट की साधना कीजिए और उसके बाद कुंभ में आकर स्नान कीजिए। इससे काफी फर्क पड़ेगा। सवाल यह है कि अगर किसी विशेष स्थान पर कोई विशेष ऊर्जा मौजूद है तो क्या आपके पास उसे ग्रहण करने की क्षमता है? क्या उसका अनुभव करने लायक काबिलियत आपके भीतर है? अगर आप इसे अनुभव नहीं कर सकते तो आप कहीं भी हों, सब बेकार है।

तो किसी खास जगह पर और किसी खास समय पर ही कुंभ लगने के पीछे एक पूरा विज्ञान है। जो पानी यहां है, वह आपके भीतर कैसे बर्ताव करेगा, उसी से आपका स्वास्थ्य और कल्याण तय होगा। इसका व्यवहार कैसा होगा? इसका व्यवहार वैसा ही होगा, जैसा आप उसके साथ व्यवहार करेंगे।

आज आधुनिक विज्ञान ने बहुत से प्रयोग किए हैं, जिससे पता चला है कि पानी की अपनी स्मृति यानी याद्दाश्त होती है। पानी के भीतर जो स्मृति और बुद्धिमत्ता है, वह जबर्दस्त है। हमें इसे समझना होगा कि यह सामान्य पदार्थ नहीं है, पानी कोई वस्तु नहीं है, यह जीवन का निर्माण करने वाला पदार्थ है। जो पानी आप पीते हैं, वह ऐसे ही कहीं नहीं चला जाता है, यह इनसान का रूप ले रहा है। इसमें स्मृति और बुद्धिमत्ता है। यह एक असाधारण अलौकिक तत्व है।

अगर आप इसे सही तरीके से लेंगे, सिर्फ तभी यह आपके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा। अगर आप इसके साथ खराब व्यवहार करेंगे तो यह भी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा।

सौजन्यः ईशा फाउंडेशन

»» कठोपनिषद कथा

ज्ञान प्राप्ति ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य

कठोपनिषद में एक सुंदर कथा है। नचिकेता और उसके पिता वाजश्रवा तथा यमराज के बीच संवाद की। जिस बालक को उसके पिता नहीं समझ पाए, उसको यमराज ने परीक्षा लेकर गुरु की तरह ज्ञान दिया। जीवन में अहंकार हमको बड़ा, सरल और प्रज्ञावान नहीं होने देता है।

कथा है कि वाजश्रवा ऐसी गायों को दान कर रहे थे, जो दूध नहीं देती थीं। इस पर पुत्र नचिकेता सवाल उठाते हैं कि इसका दान क्यों? दान में तो प्रिय और समाज के लिए उपयोगी वस्तु को देना चाहिए। नचिकेता के मन में विचार आया कि बहुतों में वह प्रथम श्रेणी के आचरण पर चले और बहुतों में मध्यम श्रेणी के आचरण का पालन करते रहे। कभी भी निचले स्तर पर आचरण नहीं किया। फिर उनके पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं?

नचिकेता ने सवाल किया कि धान की तरह यह मानव जीवन पक कर गिर जाता है और उसी की तरह फिर पैदा होता है। ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं। जब सबकुछ क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है तो जीवन को सत्य के अनुकूल बनाना चाहिए। सत्य के प्रति प्रेम के कारण नचिकेता का मन और हृदय निर्भय हो गया था। किंतु उन्हें पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में कठोपनिषद् के माध्यम से नचिकेता समय का सूर्य बनकर हमारे सामने आते हैं। क्रोध में पिता वाजश्रवा ने कहा- जा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं।

> नचिकेता सवाल उठाते हैं कि धान की तरह यह मानव जीवन पक कर गिर जाता है और उसी की तरह फिर पैदा होता है। ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं। जब सब कुछ क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है तो जीवन को सत्य के अनुकूल बनाना चाहिए। कठोपनिषद् के माध्यम से नचिकेता समय का सूर्य बनकर हमारे सामने आते हैं।

नचिकेता ने इस बात को स्वीकार किया और यमराज से मिलने चल दिए। तीन दिन की प्रतीक्षा के बाद यमराज उससे मिलने आए। तब नचिकेता की दृढ़ता और सत्य पर अडिग रहने की प्रवृत्ति से अत्यंत प्रभावित हुए और बदले में तीन वरदान दिए। नचिकेता के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में उन्हें यमराज से मिले वरदान आज

की गुरु और शिष्य परंपरा के लिए उत्कृष्ट मानदंड बन सकते हैं। यमराज हर सवाल के साथ नचिकेता की परीक्षा लेते और परीक्षा में सफल होने पर सवाल का समुचित जवाब देते।

यमराज अगर दाता के स्थान पर खड़े हों, तो कोई भी संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य मांगने का विचार करेगा! लेकिन आदर्श बालक कैसा हो, इसको भारतीय जीवन में नचिकेता ने प्रतिस्थापित किया। उसने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो और जब मैं लौटूं तो मुझे वह प्रेमपूर्वक स्वीकार करें। दूसरे वर के रूप में उन्होंने उस ज्ञान की जानकारी मांगी, जिससे स्वर्ग का सौंदर्य मनुष्य की हथेली पर होता है। इसके बाद यमराज ने नचिकेता को उस यज्ञ विद्या का ज्ञान दिया, जिसे पा लेने के बाद मनुष्य के पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन तीसरे वरदान में नचिकेता ने आत्मतत्व के बारे में पूछा। उत्तर कुछ यूं था- 'उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान्निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गं पथस्पद् कवयो वदन्ति।' कठोपनिषद् का यह मंत्र स्वामी विवेकानंद का भी प्रिय मंत्र था। उपनिषद के ऋचाकार आह्वान कर रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए।

नचिकेता का तीसरा प्रश्न मनुष्य के जिज्ञासु मन की दो परतों को खोलता है। एक जो उसकी सीमा है और प्रकृति में उलझा हुआ है। दूसरा, जो आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन का हिस्सा है। इन सवालों में जीवन की सार्थकता रहस्य है। हम जीवन के उतार-चढ़ावों में इन सवालों को भूल जाते हैं। हम अगर इंद्रियों की जगह विचारों की दुनिया में रहें, तो ऐसी प्रयोगशालाएं बन पाएंगी, जिसमें से रोज समाज के लिए नए चिंतन, नई खोज एवं नूतन दर्शन का बीजांकुर एक वटवृक्ष का रूप ले सकेगा।

डॉ. मयंक मुरारी

भारत और चीन इलेक्ट्रिक-वाहनों के निर्माण के लिए आ सकते हैं साथ

पेइचिंग। एजेंसी

विश्व के दो बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक चीन और भारत बिजली वाहनों के निर्माण में संयुक्त उद्यम के लिए उत्सुक हैं। दोनों देशों ने पेइचिंग में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में इसके लिए वार्ता की। मारुति सुजुकी, टाटा, टीवीएस जैसे भारत के दिग्गज ऑटोमेकर और उद्योग संघों ने पेइचिंग में 5वें चीनईवी100 फोरम में भागीदारी की। इस फोरम में दुनियाभर की ई-वाहन निर्माता कंपनियां मौजूद थीं। रविवार को समाप्त हुए तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन चीन ईवी100 ने किया था, जो कि चीनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उद्योग की 200 से ज्यादा दिग्गज कंपनियों का एक निजी बिजली वाहन संघ है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधान सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने चीनईवी100 के अध्यक्ष चेन किंगताई से मुलाकात की। मैकिन्से के मुताबिक, चीन बिजली वाहनों की मांग और आपूर्ति दोनों में एक दिग्गज के रूप में उभरा है। हालांकि कुछ चीनी कंपनियों का मानना है कि भारत इन वाहनों की मांग के संदर्भ में चीन को पछाड़ देगा। इससे पहले आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार में चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी सुनरा के महाप्रबंधक विक्टर लु ने कहा कि वे भारत को इलेक्ट्रिक बाइक के लिए विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरते हुए देखते हैं। फोरम को संबोधित करते हुए श्रीवास्तव ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य के रोडमैप के लिए भारत की नीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के लिए प्रतिबद्ध है और वह स्वच्छ ऊर्जा व नई ऊर्जा परिवहन के विकास व उसे अपनाने को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत द्वारा 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि दोनों देशों के ईवी उद्योगों के बीच अधिक बातचीत होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच एक औपचारिक बातचीत तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बीजिंग में इस साल की पहली छमाही में दोनों पक्षों के बीच एक बैठक करने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि सहयोग की संभावनाओं को तलाशा जा सके। श्रीवास्तव के साथ बैठक के बाद चेन ने कहा कि चीनी बिजली वाहन कंपनियों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है और उन्होंने भारतीय बाजार में चीनी उद्योगों को भागीदारी और निवेश के लिए प्रोत्साहित किया।

विद्युत क्षेत्र की मुश्किलें बढ़ीं

वितरण कंपनियों पर बकाया 26% बढ़ा

नई दिल्ली। एजेंसी

बिजली क्षेत्र में दबाव के बीच विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि इस साल अक्टूबर में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर उनका बकाया 24.7 प्रतिशत बढ़कर 39,498 करोड़ रुपया हो गया। तापीय बिजली का उत्पादन करने वाली एक कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'अगर डिस्कॉम कंपनियों पर पिछले 60 दिन के बकाये को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 50,000 करोड़ रुपये के आकंड़े को पार कर जाएगा।' वेबसाइट प्राप्ति पेमेंट रेटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्यूरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉयसिंग ऑफ जेनरेटर्स पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2017 में डिस्कॉम कंपनियों पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का बकाया बढ़कर 31,676 करोड़ रुपये हो गए। भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने पिछले साल इस वेबसाइट की शुरुआत की थी। पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कुल बकाये में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और तमिलनाडु की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। इन राज्यों के डिस्कॉम भुगतान के लिए 514 दिन से अधिक करीब एक साल चार महीने का समय लेती हैं। इनमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा (537 दिन), दिल्ली (519), महाराष्ट्र (518), कर्नाटक (517 दिन), राजस्थान (516), तमिलनाडु (515), तेलंगाना (514) और आंध्र प्रदेश (514) कुल 39,498 करोड़ रुपये के बकाए का 55 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र की ताप बिजली कंपनियों का है।इसमें अकेले एनटीपीसी का बकाया ही 15,661.31 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, एनचएपीसी को 3,011.67 करोड़ रुपए तथा दामोदर वैली कार्पोरेशन को 1990.59 करोड़ रुपए रुपए के भुगतान की प्रतीक्षा है। इसी तरह निजी क्षेत्र की कंपनियों में अडानी पावर का बिजली वितरण कंपनियों पर 6,878.94 करोड़ रुपए, बजाज समूह की ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लि का 1,861 करोड़ रुपए जीएमआर का 1630.40 करोड़ रुपए तथा सेम्बकॉर्प एनर्जी का 1,712.32 करोड़ रुपए बकाया है।

इस्पात आयात पर अंकुश की वजह से ठहर सकता है वाहन उत्पादन : सियाम

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने सोमवार को कहा कि यदि घरेलू विनिर्माताओं के आयातित इस्पात के इस्तेमाल पर अंकुश के मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकलता है तो वाहन कंपनियों के सामने उत्पादन रोकने का संकट खड़ा हो सकता है। पिछले महीने सरकार ने वाहन विनिर्माताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित स्थानीय स्तर पर उत्पादित उच्च ग्रेड के इस्पात के इस्तेमाल की समयसीमा फरवरी तक बढ़ा दी थी। वाहन विनिर्माताओं ने इसके लिए एक साल का समय मांगा है। उनका कहना है कि गुणवत्ता में निरंतरता के अभाव में उनके लिए उच्च ग्रेड के उत्पाद को हासिल करना तत्काल संभव नहीं है। सोसायटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष राजन वाधेरा ने यहां संवाददाताओं से कहा, "यह सही है कि यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं होता है तो हमारा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हम सरकार के समक्ष इस बारे में लगातार अपनी बात रख रहे हैं।" उन्होंने कहा कि वाहन विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले 90 प्रतिशत इस्पात का उत्पादन भारत में होता है। विनिर्माण में 10 प्रतिशत उच्च ग्रेड के इस्पात का इस्तेमाल होता है, जिसका उत्पादन भारत में नहीं होता। इस इस्पात का इस्तेमाल सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वाधेरा ने कहा कि इस इस्पात का आयात विदेश से किया जाता है। भारत में इसका विनिर्माण नहीं होता। हम सरकार के साथ इस मुद्दे के हल को बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्थानीय स्तर पर उत्पादित उच्च ग्रेड के इस्पात के साथ गुणवत्ता तथा निरंतरता का भी मुद्दा है। वाहन उद्योग के सूत्रों का कहना है कि बीआईएस प्रमाणन पाने के लिए विदेशी इस्पात कंपनियों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि भारत में इस्पात की बिक्री कम है। पिछले साल जून में स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात मंत्रालय ने भारत में बिकने वाले जिंसों के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य कर दिया था। यह घरेलू स्तर पर उत्पादित तथा आयातित इस्पात दोनों के लिए है।

नये डीएनए उपकरण से अपने पूर्वजों का पता कर सकेंगे

लंदन। एजेंसी

वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डीएनए उपकरण तैयार किया है जो प्राचीन लोगों की बिलकुल सटीक पहचान कर सकने में सक्षम है। साथ ही इसका इस्तेमाल इस बात के लिए भी किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति उन प्राचीन लोगों से किस हद तक मेल खाता है जो कभी धरती पर इधर से उधर घूमते रहते थे। वर्तमान में प्राचीन डीएनए के अध्ययन में किसी कंकाल का संबंध किसी निश्चित आबादी से जोड़कर बताने या उसकी जैव-भौगोलिक उत्पत्ति ढूंढने के लिए बहुत सारी सूचनाओं की जरूरत होती है।

ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के एरान एलहेक की अगुवाई में हुए इस अनुसंधान में एंसेस्ट्री इंफॉर्मेटिव मार्कर्स (एआईएम) की पहचान की गई जिनका इस्तेमाल कंकालों के वर्गीकरण के लिए किया जा सकता है। एलहेक ने कहा, 'एआईएम का प्रभावी तरीके से पता लगाने का हमने एक नया जरिया विकसित किया है और साबित किया कि यह सटीक है।' उन्होंने कहा, 'प्राचीन लोगों में आधुनिक लोगों के मुकाबले ज्यादा विविधता थी। उनकी यह विविधता नियोलिथिक क्रांति एवं ब्लैक डेथ जैसी घटनाओं के बाद कम होने लगी।' उन्होंने बताया कि विकृत डीएनए की वजह से प्राचीन डेटा को समझना मुश्किल है और इसी चुनौती से उबरने के लिए उन्होंने ऐसा विशिष्ट उपकरण विकसित किया जो पारंपरिक एवं नये तरीके के मेल से बना है। यह बेहद सटीक तरीके से पता लगा सकता है कि आप किनके वंशज हैं या आपका जीनोम रोमन ब्रिटोन्स का है या चुमाश भारतीयों का या प्राचीन इजराइलियों आदि का।

निर्यात माल पर जारी रखी जा सकती है राज्यस्तरीय करों की वापसी की योजना

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

निर्यात किए जाने वाले माल को राज्यस्तरीय करों/शुल्कों के बोझ से बचाने के लिए निर्यातक को ऐसे शुल्कों की वापसी की योजना (आरओएसएल) का लाभ रसायन और इंजीनियरिंग की वस्तुओं के निर्यात पर भी दिए जाने की संभावना है। इससे देश का निर्यात कारोबार बढ़ाया जा सकेगा। वाणिज्य मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। अभी इस योजना का लाभ श्रम-गहन कपड़ा क्षेत्र के निर्यातकों को मिलता है। इसके तहत उन्हें निर्यात माल पर राज्यों में लगने वाले स्टाम्प शुल्क, पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले करों, बिजली-कर और मंडी-शुल्क आदि की वापसी की जाती है।एक अधिकारी ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय श्रम गहन क्षेत्रों के लिए निर्यात प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रहा है और इस विषय में वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है।इसमें राज्य स्तरीय करों/शुल्कों की वापसी, जीएसटी के ऑनलाइन रिफंड की सुविधा तथा निर्यात बंधु योजना का विस्तार शामिल है। निर्यात बंधु योजना में नया-नया उद्यम शुरू करने वालों को परामर्श की सुविधा दी जाती है। वाणिज्य मंत्री ने हाल में कहा था कि निर्यातकों को भारी कठिनाई हो रही है और उनका मंत्रालय उनकी मदद करेगा। उन्होंने कहा था, "हम एक सहायता पैकेज तैयार कर रहे है ताकि निर्यातकों की समस्याओं का समुचित समाधान निकल सके।" उन्होंने यह भी कहा था, "निर्यातकों के लिए तरह-तरह की चुनौतियां काफी पहले से हैं। उनमें से एक कर्ज की चुनौती है।" निर्यातकों के शीर्ष संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गनाइजेशन्स (फियो) के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रोत्साहन से निर्यात की वृद्धि में मदद मिलेगी। वर्ष 2018-19 में निर्यात 350 अरब अमेरिकी डॉलर तक रहने की उम्मीद है। गणेश ने कहा, "जीएसटी के तहत उत्पादन के साधनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की ऑनलाइन सुविधा, अग्रिम स्वीकृति योजना तथा निर्यात संवर्धन के लिए पूंजीगत वस्तु के रियायती आयात की योजना (ईपीसीजी) और कपड़े तथा धागे के लिए भारत से वाणिज्यिक माल के निर्यात की योजना (एमईआईएस) के तहत निर्यात के दायित्वों को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।" इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईईपीसी) ने निर्यात माल पर राज्यस्तरीय शुल्कों में छूट की मांग की है। इस वित्त वर्ष में अप्रैल- नवंबर 2018-19 के दौरान निर्यात 11.58 प्रतिशत वृद्धि के साथ 217.52 अरब डॉलर रहा। पिछले वित्त-वर्ष 2017-18 में निर्यात 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 303 अरब डॉलर था।

विश्व आर्थिक मंच की बैठक में वैश्वीकरण, समावेशी वृद्धि पर होगा जोर

जिनेवा। एजेंसी

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की अगले सप्ताह होने वाली सालाना बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत केंद्रीय मंत्रियों एवं राज्यों के मुख्यमंत्री समेत भारत के 100 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। बैठक में दुनिया भर के 3,000 नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। इसमें स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति उली मारेर, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे तथा जर्मनी की चांसलर एजेंला मर्केल शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर दावोस में पांच दिन चलने वाली बैठक में इस बार चर्चा का मुख्य विषय होगा कि आर्थिक वैश्वीकरण कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकता है। साथ ही शांति, समावेशी और सतत विकास के नये माडल को पर चर्चा की जाएगी।

मिडिल क्लास को मिल सकता है तोहफा

आयकर छूट की सीमा बढ़कर होगी रु.5 लाख!

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मध्य वर्ग को राहत देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर सकते हैं, जो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो सकता है, जबकि मेडिकल खर्चों और परिवहन भत्ते को भी फिर से बहाल कर सकते हैं। इससे नोटबंदी के कारण बेहाल मध्य वर्ग को थोड़ी राहत मिलेगी।

मध्य वर्ग को लुभाने की जुगत

हालांकि, अंतरिम बजट में बहुत अधिक मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार चुनावों को देखते हुए मध्य वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसलिए टैक्स स्लैब को सुव्यवस्थित करने की योजना बनाई गई है, जो किसी भी स्थिति में आगामी प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टैक्स कोड) के अनुरूप होंगे।

हो सकता है विवाद

इसमें यह समस्या आ सकती है कि डायरेक्ट टैक्स कोड रिपोर्ट के आने से पहले आम बजट आ जाएगा। रिपोर्ट जारी होने से पहले दरों से छेड़छाड़ के कारण विवाद हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स कोड के दायरे में ज्यादा-से-ज्यादा टैक्स असेसी को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि अलग-अलग वर्गों के करदाताओं के लिए अधिक न्यायसंगत प्रणाली बनाई जाए, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की जाए और व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बनाई जाए।

मौजूदा टैक्स स्लैब

वर्तमान में 2.5 लाख रुपये की आय को निजी आयकर से छूट प्राप्त है, जबकि 2.5-5 लाख रुपये के बीच की सालाना आय पर 5 फीसदी कर लगता है, जबकि 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 फीसदी कर लगता है। हालांकि, 80 साल के अधिक की उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपये सालाना की आय पर कर छूट प्राप्त है।

40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन

इसके अलावा पिछले साल 5 लाख रुपये की आय वालों के लिए सालाना 15 हजार रुपये तक के मेडिकल खर्चों और 19,200 रुपये तक के परिवहन भत्तों को हटाकर उसकी जगह 40 हजार रुपये की मानक कटौती लाया था। इसे भी वापस बहाल किया जा सकता है। हालांकि इससे बहुत अधिक फायदा तो नहीं होगा, लेकिन मध्य वर्ग का उत्साह बढ़ेगा।

31 मार्च 2019 तक हर हाल में निपटा लें ये तीन काम, नहीं तो आपको हो जाएगी मुश्किल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही करदाता वित्तीय संतुलन बिठाने की उधेड़बुन में लग जाते हैं। नए वर्ष के पहले महीने जनवरी से लेकर मार्च तक का समय वित्त के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान आपको टैक्स बचत से लेकर तमाम ऐसे वित्तीय काम निपटाने होते हैं जो जिन्हें न करने पर आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। हम अपनी इस खबर में आपको ऐसे ही तीन कामों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको हर हाल में 31 मार्च तक निपटा लेना चाहिए।

रिटर्न में अब की देरी तो पड़ेगी भारी: आप नौकरीपेशा हों या बिजनेस मैन आपको हर वर्ष आईटीआर भरने की आदत डालनी चाहिए, यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे तो बीते वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2018 थी, हालांकि इसे 31 मार्च 2019 तक फाइन के साथ भरा जा सकता है। इसकी दूसरी डेडलाइन 31 दिसंबर 2018 थी, जिसमें 5,000 रुपये के फाइन के साथ इसे भरा जा सकता था। वहीं जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक इसे 10,000 रुपये के फाइन के साथ भरा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे भी चूक गए तो आपको इसके बाद आईटीआर भरने का मौका नहीं मिलेगा।

अपने ऑफिस को दे दें निवेश से जुड़े सभी दस्तावेज: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको हर हाल में अपने ऑफिस को साल भर के दौरान किए गए निवेश से जुड़ी जानकारी दे देनी चाहिए। ऐसा न करने की सूरत में अगर आपकी आय टैक्सेबल है तो ऑफिस आपकी सैलरी में से इसे काट लेगा। हालांकि अगर आपकी ओर से किया गया निवेश टैक्स छूट के दायरे में आता है तो आईटीआर फाइलिंग के जरिए आप इस कटौती को वापस अपने खाते में पा सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर हाल में निवेश से जुड़े दस्तावेज अपने ऑफिस को दे दें। ***फिजिकल शेयर का ट्रांसफर:*** अगर आपके शेयर्स अभी भी फिजिकल फॉर्मेट में हैं, तो उन्हें एक अप्रैल, 2019 से पहले डीमैट में बदलवा लें। अगर आपने इस समय-सीमा के अंदर अपने शेयर को डीमैट में नहीं बदलवाया, तो आप उन्हें बेच नहीं पाएंगे। यानी आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने ट्विटर हैंडल पर शुरु की 'नो योर बजट' नाम से सीरीज

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश की आम जनता को बजट की प्रक्रिया से अवगत करवाने के लिए वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें बजट से जुड़े विभिन्न शब्दों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। 'नो योर बजट' सीरीज

आम बजट के महत्व को और इसकी प्रक्रिया को समझाएगी और यह सिलसिला पूरे पखवाड़े चलेगा।

केंद्र सरकार एक फरवरी को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि आगामी कुछ महीनों में आम बजट पेश किया जाना है। इस वित्त वर्ष के लिए पूर्ण बजट आगामी गठित होने वाली नई सरकार की ओर से पेश किया जाएगा। मंगलवार को वित्त मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से शुरु की गई यह सीरीज बताएगी कि आम बजट क्या होता है और वोट ऑन अकाउंट (लेखानुदान) क्या होता है।

बजट को लेकर मंत्रालय ने समझाया, 'बजट केंद्र सरकार के वित्तीय लेनदेने की जानकारी देने वाली सबसे विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें सरकार के सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व औकर विभिन्न गतिविधियों के लिए आवंटित व्यय की जानकारी होती है।'

बजट को लेकर मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया, 'बजट में सरकार के अगले वित्त वर्ष के आय-व्यय के अनुमान भी दिए जाते हैं, जिन्हें बजट अनुमान कहा जाता है।' वहीं वित्त मंत्रालय ने वोट ऑन अकाउंट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह संसद की ओर से अगले वित्त वर्ष के अगले हिस्से में किए जाने वाले खर्च की अग्रिम अनुमति देता है।

लाजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए अलग विभाग बने- सलाहकार परिषद

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने देश में परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा कारोबार को आसनी बढ़ाने के लिए सरकार के अंतर्गत अलग से एक लाजिस्टिक्स विभाग खोलने और ट्रकों के लिए पूरे देश में "एक परमिट, एक कर" प्रणाली लागू करने जैसे कई सुझाव दिए हैं। ईएसी-पीएम के चेयरमैन विवेक देवराय की अध्यक्षता में लाजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास के उपायों पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने अपनी रपट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में ही सौंपी है। इसका शीर्षक है 'की चैलेंजेज इन लाजिस्टिक्स डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड कामर्स- पालिसी रिफार्म फार ईज आफ डूइंग बिजनस एंड ट्रेड इन इंडिया" (लाजिस्टिक्स विकास और संबंधित वाणिज्य- भारत में कारोबार/व्यापार सुगमता के लिए नीतिगत सुधार) है। ट्रक परिवहन उद्योग की मदद की आवश्यकता पर बल देते हुए रपट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को लाजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा पर ध्यान देने के लिए एक अलग विभाग बनाना चाहिए। इसके लिए वाणिज्य विभाग के तहत काम कर रहे लाजिस्टिक्स विभाग का दर्जा बढाने की सिफारिश की गयी है। समिति ने सिफारिश की है कि संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप " मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित कर पूरे देश में ट्रकों के लिए एक देश, एक परमिट, एक कर प्रणाली लागू की जाए।" रपट में मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा संशोधन करने की सिफारिश भी की गयी है ताकि ट्रक परिवहन इकाइयां अपने परिचालन का विस्तार करने को प्रोत्साहित हों।" एक परमिट प्रणाली में ट्रक अपने परमिट पर देश भर में कहीं भी माल ले जा सकेंगे। समिति ने रेलगाड़ियों के माल भाडे के ढ़ांचे को भी तर्कसंगत बनाने की भी सिफारिश की है। उसका कहना है कि यह काम पहले पायलट आधार पर कुछ चुनिंदा मार्गों (उदाहरण के लिए दिल्ली-जेएनपीटी और दिल्ली-मूंद्रा बंदरगाहों के रास्तों) पर पायलट आधार पर शुरू किया जा सकता है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।